

खबर संक्षेप

जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत चार क्लस्टरों में होने सामूहिक विवाह

मण्डला। जिले में वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशानुसार जिले में चार क्लस्टर बनाकर पात्र कन्याओं के विवाह संपन्न कराए जाएंगे। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम क्लस्टर में जनपद पंचायत मंडला के साथ नगर पालिका मंडला और जनपद पंचायत मोहगांव शामिल होंगे। द्वितीय क्लस्टर में जनपद पंचायत नैनपुर, नगर पालिका परिषद नैनपुर तथा नगर पंचायत बम्हनीबंजर शामिल हैं। तृतीय क्लस्टर में जनपद पंचायत बिछिया के साथ जनपद पंचायत मवई, नगर पालिका परिषद बिछिया तथा जनपद पंचायत घुघरी को शामिल किया गया है। वहीं चतुर्थ क्लस्टर में जनपद पंचायत निवास, नगर पंचायत निवास, जनपद पंचायत बीजांडी तथा जनपद पंचायत नारायणगंज शामिल रहेंगे। योजना के तहत प्रत्येक क्लस्टर में 200 पात्र कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इस प्रकार जिले में कुल 800 जोड़ों को योजना का लाभ मिलेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास और घुघरी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने पात्र परिवारों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन करें। इच्छुक परिवार संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय या सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क कर निर्धारित तिथि और स्थान के अनुसार आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

जल्दी रेत पहुंचाने पर मिलाता चालकों को विशेष इनाम

बेलगाम भागते रेत के डंपर लोगों की ले रहे जान

* निरंकुश ठेकेदारों पर क्या शासन-प्रशासन लगायेगा नकेला।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

नियम कानून की यदि धजिया उड़ती देखना हो तो आप मंडला आइए यहाँ देखिए किस तरह नर्मदा तट पर प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले के साथ शराब का विक्रय एवं परिवहन गली-गली हो रहा है किस तरह से इस पवित्र नगरी में खुले में मांस एवं मछली का विक्रय हो रहा है किस तरह से इस माहिष्मती नगरी में जिसे माँ नर्मदा का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है वहाँ कैसे माँ नर्मदा की धारा प्रवाह को रोक दिया जाता है कैसे माँ नर्मदा के जल के अंदर बड़ी-बड़ी मशीनों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है कैसे माँ नर्मदा के जल में सैकड़ों टॉली मिट्टी मुरम डालकर उस पर से बड़े-बड़े वाहन धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और यह सब उस सरकार के राज्य में हो रहा है जो अपने आप को नर्मदा भक्त होने का दावा करती है उस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है जो महीने में



10 बार माँ नर्मदा की पंचचौकी आरती में जाकर नतमस्तक होता है।

एक समय वह भी प्रशासन था जिसने इन रेत के डंपरों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था किसी भी स्थिति में रेत के खाली या भरे डंपर शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाते थे और तो और उनके द्वारा डंपर के माध्यम से रेत के परिवहन को भी बंद कर दिया गया था लेकिन आज का प्रशासन इसका उल्टा कर रहा है आज ट्रैक्टर ट्रालियां तो पकड़ ली जाती हैं लेकिन डंपर को छूने की भी हिम्मत किसी अधिकारी की नहीं हो

पा रही है। रेत ठेकेदार द्वारा उन चालकों को विशेष रूप से नगद इनाम दिया जाता है जो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा रेत परिवहन करता है और इसी इनाम के लालच में उक्त डंपर का चालक लगातार रेत परिवहन करने में लग जाता है और इस दौरान ना तो वह पूरी तरह सो पाता है और ना ही उसकी नींद पूरी हो पाती है यही कारण है कि अधुरी नींद के चलते डंपर की गति अनियंत्रित हो जाती है और दुर्घटना का कारण बनती है जब तक रेत डंपर में लोड हो रही होती है तब तक यह डंपर का

चालक शराब का मजा लेते रहते हैं और यह शराब भी रेत के ठेकेदारों द्वारा खदान स्थल पर इन्हें उपलब्ध कराई जाती है और शराब के नशे में चालक जब डंपर की स्टीरिंग संभाल लेता है तो फिर उसे किसी का डर नहीं होता सड़क पर चलने वाले उसे कीड़े मकौड़े की तरह नजर आते हैं और यही कारण है की दुर्घटनाएं हो रही हैं।

इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के पूरे जीवन की खुशी छीन गई, किसी की जिंदगी भर के सपने टूट गए, किसी की गोद सूनी हो गई। इन्हें तो अपने व्यापार और अपने पैसे से ही मतलब है।

यह बात सही है कि प्रत्यक्ष रूप से इन दुर्घटनाओं में वाहन मालिक एवं रेत ठेकेदार की कोई गलती नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह दोनों ज्यादा जिम्मेदार हैं यदि डंपर का मालिक चालक को हिदायत देकर रखता कि ज्यादा गति से डंपर नहीं चलाना है गति नियंत्रित रखना है समय पर परिवहन करके आराम करना है।

आज के समय में जबकि

जीपीएस सिस्टम एवं दूसरी तकनीक है जिसके माध्यम से पूरे समय हम अपने वाहन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा वाहन किस समय कहाँ पर है और किस स्थिति में है चालक से बात भी हर समय की जा सकती है यदि लगातार मालिक इनके संपर्क में रहते और इन्हें हिदायत देते रहते तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

रेत से भरे इन डंपरों की ना तो रॉयल्टी चोक की जाती है और ना ही इन वाहनों के कागजात देखे जाते हैं एक ओर तो परिवहन विभाग के कथित अधिकारी कर्मचारी मंडला जबलपुर हाईवे में चोरों की तरह छुपकर ट्रक चालकों को अपना शिकार बना रहे हैं वहीं इसी हाईवे से जब रेत के भरे डंपर निकलते हैं तो कभी भी इन्हें रोक कर यह नहीं देखा जाता कि इन वाहनों का बीमा है कि नहीं, इनका फिटनेस है कि नहीं, इनको पर्यावरण की अनुमति है कि नहीं, इनमें नंबर प्लेट लगी है कि नहीं, रेत परिवहन की जा रही है इसकी रायल्टी है कि नहीं और है तो कितनी अवधी की है।

इसके साथ ही यह कोई बताने वाला नहीं कि गीली रेत परिवहन की आखिर इन्हें अनुमति किसके द्वारा दी गई है रेत से भरे डंपर जब सड़क पर चलते हैं तो इतनी मात्रा में पानी गिर रहा होता है कि सड़क गीली हो जाती है ऐसे में पीछे चल रहे वाहन के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है लेकिन इन खतरों से प्रशासन को क्या लेना देना इन्हें तो नर्मदा भक्ति की आड़ में लक्ष्मी की पूजा करना है और यह काम इन्हें ज्यादा भा रहा है लेकिन जिस दिन भी नर्मदा जी की दुष्टि वक्र हुई उस दिन फिर ना तो लक्ष्मी की कृपा रहेगी और ना ही भोलेनाथ इन्हें बचाने वाले हैं।



नारायणगंज में सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न



हरिभूमि न्यूज | मण्डला

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और नवांकुर संस्था जन कल्याण सेवा सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में विकासखंड नारायणगंज में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण

कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक संतोष झरिया ने परिषद की संरचना, भूमिका, आयाम एवं समग्र ग्राम की विकास की अवधारणा पर विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण में पधारे अतिथियों का

पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। प्रशिक्षण के दौरान समग्र ग्राम विकास की अवधारणा विषय पर सत्र लिया गया। नवांकुर संस्था जन कल्याण सेवा सोसाइटी बीजेगांव के द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सीईओ जिला पंचायत ने बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन केन्द्र का किया निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला क्रमांक 2 में हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना ने मूल्यांकन कार्य का जायजा लिया। उन्होंने केन्द्र में मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों की ड्यूटी, बैठक व्यवस्था, माडल आन्सरशीट, मूल्यांकन कर्ताओं के जलपान, स्ट्रॉगरूम और सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी ली। इस दौरान जिला शिक्षा



अधिकारी श्रीमती मुन्नी वरकडे ने सीईओ को बताया कि इस मूल्यांकन केन्द्र में दसवीं तथा बारहवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 9 कक्षा में किया जा रहा है। जिले के विद्यार्थियों से 232 शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी तक

बारहवीं की 46564 और दसवीं की 55065 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा यहाँ भेजी गई हैं, अभी और कॉपियां आनी शेष हैं। इस दौरान एपीसी श्री मुकेश पाण्डे, बोर्ड परीक्षा प्रभारी महेंद्र श्रीवास एवं संबंधित शिक्षक मौजूद रहे।

16 मार्च को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

मण्डला। जिला प्रशासन मण्डला द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक जिला योजना भवन में आयोजित की जाएगी। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह बैठक सोमवार को साप्ताहिक समय-सीमा बैठक की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिसमें जिले की सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

अनदेखी

स्कूल और आंगनबाड़ी के सामने खतरनाक ढलान।

छोटे बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

* मंडला-डिंडौरी सड़क निर्माण के दौरान बन गया ढलान।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

मंडला-डिंडौरी मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान रसेयादौना स्थित स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के सामने बनाया गया ढलान छोटे बच्चों के लिए खतरा बनता नजर आ रहा है। यहां कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में भी छोटे-छोटे बच्चे प्रतिदिन आते-जाते हैं।

जानकारी के अनुसार मण्डला डिंडौरी सड़क निर्माण के कारण सड़क का स्तर पहले से काफी ऊंचा कर दिया है। ऐसे में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर निर्माण एजेंसी द्वारा मुरुम और पत्थर डालकर अस्थायी ढलान बना दिया गया है, ताकि बच्चों का आवागमन हो सके। लेकिन यह ढलान काफी ऊंचा होने के साथ ही पत्थर और मुरुम से बना है, जिससे बच्चों के फिसलने और गिरकर चोटिल होने की आशंका बनी रहती है। कई बार बच्चे इस ढलान पर फिसलकर गिर भी चुके हैं।



हैरान करने वाली बात यह भी है कि सड़क निर्माण के दौरान स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ कर छोड़ दिया गया है, जिससे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों और शाला प्रबंधन का कहना है कि उन्हें सड़क निर्माण कार्य से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के सामने बनाया गया ढलान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाना

चाहिए। वर्तमान स्थिति में यह ढलान बच्चों के लिए असुरक्षित साबित हो रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शाला प्रबंधन के अनुसार इस समय बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिसके कारण सभी विद्यार्थियों का स्कूल आना अनिवार्य है। ऐसे में प्रतिदिन बच्चों को इसी खतरनाक ढलान से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे अजिबभावकों और शिक्षकों में चिंता बनी हुई है।

इनका कहना है -

रोड निर्माण कार्य से हमें किसी

प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि स्कूल तक पहुंचने वाला मार्ग व्यवस्थित रूप से बनाया जाए ताकि बच्चों को स्कूल आने-जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया है।

—श्रीमती नमिता श्रीवास्तव, शिक्षक, शा. मा. वि. रसेयादौना, मण्डला

मुर्दों से भी इनको डर नहीं इनके रास्ते में भी हो रहा भ्रष्टाचार

* फर्जी बिलों की राशि का हो रहा बंदरबांट।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

सभी की अंतिम यात्रा इसी रास्ते से गुजरती है इस मार्ग में कोई व्यवधान न हो ये सब की जिम्मेदारी है लेकिन मंडला जनपद की ग्राम पंचायत भपसा में शमशान तक जाने वाले मार्ग पर 7 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत पुलिया कम स्टाफडेम की राशि निकाल ली गई है और लगभग 1 वर्ष हो रहे हैं निर्माण कार्य आज भी अधूरा है जिससे शव यात्रा का सफर घुमावदार हो गया है यहां के पंच अंकित कछवाहा, श्याम सिंगौर



एवं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सरपंच एवं उपसरपंच पतियों की मनमानी के चलते यहां की नाली एवं अधिकांश अन्य निर्माण कर गुणवत्ता विहीन कराई जा रहे हैं। जिसकी शिकायत लगातार उच्चाधिकारियों से की जा रही है लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है बताया गया की

सरपंच एवं उपसरपंच पतियों के खाते में पंचायत की फर्जी राशि डाली गई है और सारे नियमों को ताक में रखकर फर्जी बिलों से राशि निकाल कर बंदरबांट किया जा रहा है। पंचायत के जिम्मेदारों को किसी जांच का डर नहीं है यहां कागजों में सब खेल खेला जा रहा है ग्रामीणों को तो छोड़िए यहां पंचायत के निर्वाचित पंचों को भी कुछ नहीं बताया जाता पारदर्शिता का अभाव बना हुआ है शिकायत से हारे थके ग्रामीणों द्वारा अब आज पास के ग्राम हिरदनगर में एक धार्मिक कार्यक्रम में पधार रहे जिले के प्रभारी मंत्री से आग्रह किया गया है कि थोड़ा देर के लिए आकर हमारे पंचायत के निर्माण कार्यों को भी देख लें तो कृपा होती।



खबर संक्षेप

इस तरह की लापरवाही जन्म देती है घटनाओं को
हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। शहर के रेलवे स्टेशन पर रेलयात्री सुविधाएं मांगने के हकदार हैं किन्तु जान जोखिम में डाल उनका ट्रेनों में सफर करने को आतुर रहना उचित नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि इन दिनों चुनावी महौल के कारण रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों पर रेलयात्री बच्चों, युवाओं, महिलाओं की काफी भीड़भाड़ का आलम रहता है, इस दौरान जब भी कोई ट्रेन रुकती है तो उसमें सीट सुरक्षित करने के लिए अधिकतर यात्री अपनी जान की परवाह न कर सीट की जुगाड़ में लग जाते हैं। हालात यह हैं कि कभी रुकने के लिए रंगती ट्रेनों में उनके द्वारा चढ़ने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कई रेलयात्री ट्रेनों में सीट सुरक्षित करने के चर्चों में ट्रेक पर खड़े हो जाते हैं। जब प्लेट फार्म कूद ट्रेक पार करना अपने आम में खतरों से खाली नहीं रहता, शहरवासियों ने रेल पुलिस से गुहार लगायी है कि स्टेशन पर ट्रेनों के आने के समय वह प्लेटफार्मों पर विशेष चौकसी बरते और रेलों में जगह पाने के लिए ट्रेक का इस्तेमाल करने वाले रेलयात्रियों को ट्रेक से हटा प्लेट फार्मों पर ही बैठकर ट्रेनों में चढ़ने की हिदायत दें।

स्वर्चि मोज अब गांवों में भी बना फैशन, लाखों के अन्न की हो रही बरबादी
हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। कुछ साल पहले तक गांव देहातों में जिसे गिद्धभोज की संज्ञा देते हुये सुना जाता था वह बफर सिस्टम अब गांवों में भी एक रूप से रिवाज बन चुका है? जो लोग आज हमारे हिन्दू धर्म की परम्परा के अनुसार पंगत से यानि प्रतिभोज कराते हैं उन्हें लोग हीन भावना से देखने लगे हैं? यहां तक की गांव कस्बों में भी स्वर्चि भोजन न पंगत का स्थान ले लिया है, कहते हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, जिसकी हमारे मध्यमवर्गीय समाज में निहायत कभी नजर आती है? नतीजा यह है कि जिस देश में करोड़ों लोग दाने- दाने को मोहताज हैं, उसी देश में आज के समय में शादियों और इस तरह के अन्य समारोहों में आयोजित होने वाले बफर यानि स्वर्चिभोज में लोग बेरहमी से तमाम खाद्य पदार्थ प्लेटों में भरकर और आधा अधूरा खाकर हजारां रूपये के खाद्य पदार्थ यानि की अन्न देवता की बरबादी कर रहे हैं। जबकि सही मायने में देखा जावे तो उस भोजन अन्न के लिए आज भी कई परिवार महंगाई के दौर में तरस रहे हैं? आमतौर पर कुछ समय पहले तक हमारे देश में लोग पंगत में बैठकर खाने को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, मगर अब लोगों ने अपनी फेरमन के चलते उसे भूलकर बफर में खड़े होकर खाने को अपना सम्मान समझने लगे हैं? चाहे घनाद्वय वर्ग हो या मध्यमवर्गीय परिवार इस भोज को उसने अपनाया है और लोगों के सामने अपनी हेमियत दिखाने के लिए वह तरह तरह के व्यंजन बफर में रखता है और लोगों के जीभ में व्यंजन देखकर पानी भर आता है और लोग असतान की हद तक जाकर अपनी प्लेटों में खाना तो भरपूर खा लेते हैं पर खा नहीं पाते और उस खोड़ी देर बाद पास में पड़े डिब्बे में छोड़ देते हैं

कई किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पैदल चलकर जनजातीय बाहुल्य ग्राम बड़ागांव में पहुंची कलेक्टर, जनसंवाद शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, आमजन की सुविधा के लिये अगले सप्ताह शुरू होगा मार्ग निर्माण कार्य



हरिभूमि न्यूज/ गाइरवारा।

तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल क्षेत्र में अनेक इस तरह के गांव हैं जहां पर वाहन से पहुंचने की बात तो दूर पैदल तक पहुंच पाना मुश्किल होने से नही चूकता है। मगर इन गांवों में जब अधिकारी पहुंचते हैं तो लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई देने से नही चूकती है। कुछ इसी प्रकार से बीते हुये दिवस समीपस्थ गोटीटोरिया जंगल क्षेत्र के पहुंच बिहीन गांवों में जब जिला कलेक्टर पहुंची तो वहां का महौल अनेखा देखने मिला। बताया जाता है कि दुर्गम पहाड़ी पर स्थित जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत मोहपानी के आदिवासी बाहुल्य ग्राम बड़ागांव में शनिवार को जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया। इस गांव में मुख्य रूप से भारिया जनजाति के नागरिक निवास करते हैं। शिविर का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना तथा उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। दुर्गम मार्ग होने के कारण कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य अधिकारी लगभग 12 किमी दूरी पहाड़ों पर पैदल चलकर भारिया जनजातीय बाहुल्य ग्राम बड़ागांव पहुंचकर वहां के निवासियों से सीधे संवाद किया। शिविर में कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित



अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि गांव तक पहुंच मार्ग की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान संबंधित अधिकारी ने अवगत कराया कि आगामी सप्ताह में बड़ागांव तक पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को स्वसहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों के माध्यम से आटा चक्की, मुर्गी पालन, बकरी पालन सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं अपनी आय बढ़ा सकती हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आगामी 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में ग्रामीणों को जल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से जल संरक्षण करने पर गांव में पानी की समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा। कलेक्टर ने शिविर में हर घर जल मिशन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण कार्यक्रम, आंगनवाड़ी सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाटरशेड एवं जल संरक्षण आदि योजनाओं, कार्यक्रमों व गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जनसंवाद शिविर में विभिन्न विभागों के

अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वही कृषि विभाग के उप संचालक मोरिस नाथ ने किसानों को विभागीय योजनाओं एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. सुनील बृजपुरिया ने मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौवंशीय पशुपालन सहित पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। सीएचओ गोटीटोरिया सौम्या ब्रह्मण ने आयुष्मान कार्ड, गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण अभियान सहित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही आधार, समग्र आईडी और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रियाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। शासन के आदेश पर आयोजित किये गये इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं, बुजुर्गों, नागरिकों और बच्चों का मौके पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने ग्राम बड़ागांव के आंगनवाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चों तथा कुपोषित बच्चों की जानकारी ली और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर को अवगत कराया गया कि गांव में एक बच्चा कुपोषित पाया गया है। कलेक्टर ने तत्काल

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक व सीएचओ को निर्देशित किया कि उक्त बच्चे के घर जाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करें और आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस दौरान कलेक्टर स्वयं सेम बच्चे के अभिभावक को समझाशा देने के उद्देश्य से उनके घर पहुंची। घर पहुंचकर कलेक्टर ने बच्चे के अभिभावक को समझाशा दी कि बच्चे को एनआरसी में भर्ती कराने से उसे उचित उपचार और पोषण मिल सकेगा तथा वह जल्द स्वस्थ हो जाएगा। कलेक्टर की इस समझाशा पर अभिभावक ने बच्चे को एनआरसी में भर्ती कराने के लिए सहमति व्यक्त की गई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत ग्राम बड़ागांव में निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राही मोहन भारिया, शंकर भारिया एवं विनोद भारिया के आवासों का अवलोकन किया और निर्माण कार्य की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान हितग्राही मोहन भारिया का आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर ने आवास का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्य की सराहना की और हितग्राही से संवाद कर योजना के संबंध में जानकारी ली। वहीं हितग्राही श्री शंकर भारिया, श्री विनोद भारिया एवं एक अन्य हितग्राही के आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।



पतरोई जलाने पर अंकुश न लगना बन रहा परेशानी का कारण

हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण को लेकर न तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और न ही आम लोगों द्वारा जिसका परिणाम यह जान पड़ने लगा है कि क्षेत्र की स्थिति एक दिन इस प्रकार से बन जावेगी जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में निर्मित होते हुये देखी जा रही है, क्योंकि इस समय किसानों के खेतों में गन्ना कटाई का कार्य पूर्ण होने के बाद जहां किसानों द्वारा अपने खेतों को खाली करने के लिये खेतों में पड़ी हुई गन्ने की पतरोई को धडल्ले से जलाया जा रहा है, वही दूसरी ओर क्षेत्र की शूगर मिलों में काम करने के लिये बाहर से आये हुये लोगों द्वारा भी अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये गन्ने की फसल को पहले आग के हवाले करते हुये कटाई की जा रही है। इस प्रकार से गन्ने की पतरोई को जलाने का परिणाम है कि नगर सहित संपूर्ण क्षेत्र में गन्ने की जली हुई पतरोई के कारण दिन भर कालिख उड़ते हुये देखी जा रही है जो लोगों की छातो सहित मुख्य मार्गों पर पड़ी हुई आसानी से देखी जा सकती है। बताया जाता है कि बाहर से आये हुये गन्ना काटने का कार्य करने वाले लोगों द्वारा काटे गये गन्ने से पत्ते हटाने में होने वाली परेशानी से निजात पाने के लिये पहले उसमें आग लगा दी जाती है जिसके चलते सूखे पत्ते जल जाने से गन्ने की कटाई करने में सुविधा होती है, इस प्रकार से अपने स्वार्थों के चलते जहां खुलेआम पर्यावरण से खिलबाड़ की जा रही है। वही दूसरी ओर कुछ किसानों द्वारा भी अपने खेतों को खाली करने की सोच रखते हुये खेतों में पड़ी हुई गन्ने की पतरोई को धडल्ले से जलाया जा रहा है, इस प्रकार से खेतों में पड़ी हुई पतरोई के जलाने पर प्रतिबंध लगना जरूरी हो गया है यदि समय रहते हुये ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा क्षेत्र में दिल्ली के समान दिनों में देर नहीं लगी और लोगों को सांस लेने के लिये शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो जावेगा?

नेशनल लोक अदालत में हुआ आपसी सहमति के बीच सैकड़ों प्रकरणों का निपटारा, पर्यावरण की रक्षा का संदेश देते हुये वन विभाग द्वारा पौधों का किये वितरण



हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। लोगों को आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिये समय समय पर जिला विधिक सेवा द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते बीते हुये शनिवार को स्थानीय न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ न्यायाधीश मा. श्रीमति संतोषी वासनिक जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा सिविल न्यायालय गाइरवारा में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यापण एवं दीप प्रचलित करते हुये किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मा. सूरज सिंह शटीड चतुर्थी जिला न्यायाधीश, मा. राजेश कुमार तिवारी प्रथम जिला न्यायाधीश, मा. पंकज जायसवाल तुलिया जिला न्यायाधीश, मा. राम प्रकाश अहिरवार षष्ठम

जिला न्यायाधीश, मा. अजय सिंह यादव अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, मा सुश्री कृति का सिंह जे.एम.एफ.सी. गाइरवारा, मा. विनय सोनी, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मा. यश शर्मा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कनिष्ठ खंड गाइरवारा के आलवा अधिवक्ता संघ अध्यक्ष हिमांशु दुबे के आलवा उपाध्यक्ष व सचिव एवं अधिवक्ता बसंत तपा सहित अन्य अधिवक्ता गण एवं बैंको के अधिकारी, विद्युत विभाग से आये हुये अधिकारियों के आलवा नगर पालिका एवं न्यायालय कर्मचारी स्टाप विधिक सेवा से पीएलबी मौजूद रहें। इस दौरान नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करते हुये न्यायाधीशों ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना है। इसी लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों

का निपटारा किया जाएगा, जिनमें दीवानी वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना के मामले, बैंक रिकवरी और चेक बाउंस के मामले शामिल हैं। जिसमें बैंक बिजली विभाग नगर पालिका ने अपने स्टाल लगाए जहां आपसी समझौते के आधार पर लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। आयोजित हुई लोक अदालत में बनी खंडपीठों द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों का समझौते के साथ निराकरण किया नेशनल लोक अदालत के दौरान रखे गये प्रकरणों में 203 में से निराकृत प्रकरण 192 जिनकी राशि जमा हुई 72055024 रूपया तथा लाभांविता व्यक्ति 331। इसी प्रकार से प्रिलिटिगेशन विद्युत प्रकरण रखे गये प्रकरण 152 में से निराकृत प्रकरण 152 तथा राशि जमा हुई 1948678 रूपया और लाभांविता होने वाले लोगों की संख्या 152 रही। वही

अप डाउन संस्कृति पर नहीं लग पा रही रोक, शासन की योजनाएं हो रही फेल, मनमर्जी के मुताबिक संचालित होते हैं शासकीय कार्यालय...?

हरिभूमि न्यूज/साईखड़ा। जहां एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाकर आमजन तक पहुंचाने के लिए शासकीय विभाग बनाये गये हैं और इन शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से ही लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, मगर देखा जा रहा है कि शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों की उदासीनता कही जावे या फिर उप डाऊन करने की प्रवृति में लिप्त मनमानी के चलते शासन की योजनाओं का जहां समय पर लोगों को लाभ नहीं मिल पाने की स्थिति में समस्त योजनाएं फेल होते हुए जान पड़ने लगी है? जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो ब्लाक मुख्यालय के अंतर्गत जितने भी कार्यालय है उनमें चंद अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़ दिया जावे तो अनेक अधिकारी ऐसे हैं जो अप डाउन संस्कृति को न अपनाये हो...? यहां के अनेक शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की अप डाऊन संस्कृति के चलते शासन की योजनाएं फेल होती जा रही है...? यहां पर अनेक विभाग के कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी तक अप डाऊन कर रहे हैं? इतना ही नहीं यहां के प्रमुख ब्लाक कार्यालय व पुलिस थानों के साथ साथ स्कूलों में पदस्थ प्राचार्य सहित तहसील कार्यालय व अन्य विभागों के अधिकारियों सहित अनेक कार्यों में का यह हाल चल रहा है...? और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा है कोई कार्यवाही न होने के कारण अधिकारी अपनी मनमानी से कार्य करते आ रहे हैं? जब मन करस आ जाते हैं जब मन करे तब चले जाते हैं कोई रोकने वाली नहीं है...? यह बात जरूर है कि यदि ऐसा कोई छोटा कर्मचारी करे तो नोटिस जारी होने लगते हैं। लेकिन जो उस विभाग का मुखिया होता है उस पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं रहता? लेकिन आज तक कोई भी जिला स्तर के अधिकारी द्वारा इस अप डाऊन संस्कृति के रवेया को अपनाने वाले अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं? जिसके कारण अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों का खुलने व बंद होने का जो समय

निश्चित किया गया है, उस समय पर न तो वह कार्यालय पहुंच पाते हैं और न ही लोगों की समस्याओं को सुना जाता है...? जिसके कारण आम जनता की समस्या का हल नहीं निकलता व शिकायतें दिनों दिनों बढ़ती जाती हैं...? मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार को शुरू किया गया जनसुनवाई कार्यक्रम भी अधिकारियों को याद नहीं रहता है? जिसके कारण जनसुनवाई भी नहीं हो पाती है और उस दिन जनता कार्यालयों के पास अपनी समस्या को लेकर मंगलवार के दिन का इंतजार करती है और अपना अपना काम छोड़ कर जनसुनवाई के निश्चित समय 11 बजे के पहले इन कार्यालयों में आ जाते हैं और साहब के आने का इंतजार करते रहते हैं? लेकिन जब उन्हें मालूम चलता है कि साहब अभी आये ही नहीं है इस स्थिति में क्षेत्र लोगों को निराशा ही हाथ लगती है? अगर कोई उस कार्यालय में मौके पर उपस्थित किसी चपरसी से पूछे तो वह भी यही कहे देता है कि जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है? साहब को सप्ताह के अन्य दिन वैसे ही मंगलवार का रहता है, साहब उसी समय पर आयेगे जिस समय ट्रेन आएगी, साहब भी बेचारे क्या करे वह तो आना चाहते हैं पर ट्रेन लेट हो जाती है जिस कारण साहब समय पर आफिस नहीं पहुंच पाते हैं? जब ट्रेन या फिर अन्य वाहन गाइरवारा आयेगा और फिर साहब यहां आयेगे? जिससे कार्य प्रभावित होते हैं तो होते रहे अब अपने परिवार थोड़ी छोड़ देवे? यह हाल एक ही कार्यालय का नहीं बल्कि ब्लाक व तहसील स्तर से लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी देखा जा रहा है? क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि यहां के शासकीय कार्यालयों का यही हाल रहा तो क्या शासन की योजनाएं वह जनता की समस्याओं का हल हो पायेगा? अगर शासन प्रशासन को शासन की योजनाओं को जन जन तक लाभ पहुंचाना है तो सबसे पहले अप डाऊन संस्कृति पर रोक लगाया होगा? अगर इस संस्कृति पर रोक लग गई तो आम जनता के काम वाकई में समय सीमा में होने लगेगे, और आम जनता भी राहत की सांस लेगी, ऐसी शासन प्रशासन से अपेक्षा है।

चीचली क्षेत्र के वीरान इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों देर रात तक खुलेआम जाम छलकते हुये देखे जा रहे हैं जाम

हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा। समीपस्थ चीचली क्षेत्र में चल रहे शराब के अवेध कारोबार का परिणाम है कि लोगों को गांव गांव जहां खुलेआम मेढनों से लेकर सरकारी भवनों में शराब पीने के अड्डा बनने के कारण अहाते के रूप में दिखाई देने से नही चूक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहां पूर्व के समय में लोग शराब पीने के लिए ऐसी जगह खोजते थे जहां पर किसी की नजर न पड़े। मगर इस समय तो स्थिति इस प्रकार से देखने मिल रही है कि लोगों द्वारा जहां तहां बैठकर शराब का सेवन करते हुये नशे की हालत में सड़कों पर घूमते हुये आसानी से देख जा सकता है...? इतना ही नहीं यदि गौर किया जावे तो वर्तमान में अजयनगर शहर लेकर गांवों के 60 प्रतिशत युवाओं और किशोरों में शराब पीने का शौक ऐसा लगा है कि वे रात को बिना जाम छलकते रहे ही नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते वे सामी क्षेत्रों में वीयरवार न होने और अधिकांश स्कूलों से लेकर सरकारी भवनों सहित ढावों में शराब के जाम छलकाने के लिए उपयुक्त जगहों शराब खोरी करने से नही चूक रहे हैं। वहीं खुलेआम नगर के पास पास बने हुये ढावों में देर रात तक शराब खोरी होने के नजारे देखने मिल रहे हैं...? पुलिस की उदासीनता के चलते चीचली क्षेत्र में गांव गांव वल रहे शराब के अवेध कारोबार का परिणाम है कि जहां अपने आपकों वीर बनते हुये शांति व्यवस्था को भंग करने के कारण पटरी से उतरती हुई कानून की स्थिति निर्मित होते हुये देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाये भी आम बात बनने से नही चूक रही है। गौर किया जावे चीचली क्षेत्र में इन दिनों शराब के शीतियों को बंद रही तादत के चलते नगर के अनेक जगहों में जहां खुलेआम शराब की विक्री होने के साथ साथ यहां पर देर रात तक शराब पीने वालों की



दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल गाइरवारा
CBSE बोर्ड आधारित, DPIS Org. नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त
कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवीं तक DPIS प्रवेश प्रारंभ
दिवेकानंद पार्क, शनि मंदिर के पास, साईधाम कॉलोनी, गाइरवारा, जिला नरसिंहपुर
Mob. : 903 9230 199, 722 4021 199 Email- dpsgadarwara@gmail.com

खबर संक्षेप

उल्लास नवभारत साक्षरता परीक्षा आयोजित



डिंडोरी। जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नव साक्षरों की मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु के नव साक्षरों ने भाग लिया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जिले को 30000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में कुल 1250 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का संचालन कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निदेशन में किया गया। इसी क्रम में जिला परियोजना समन्वयक श्वेता अग्रवाल ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एकीकृत माध्यमिक शाला देवरा मुड़कों लुकामपुर और धुराई केंद्रों का दौरा किया गया। इस दौरान शौचालय व्यवस्था मध्याह्न भोजन स्थानीय परीक्षा संचालन एचपीवी टीकाकरण तथा विद्यालय परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। विद्यालय परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई और संबंधित जिम्मेदारों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला साक्षरता सह समन्वयक ब्रह्मनंद झा तथा विकासखंड सह समन्वयक जवाहर ठाकुर भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।

कृषकों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण



डिंडोरी। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उद्योगिनी संस्था और कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में विकासखंड करजिया की महिला उद्यमी समूहों को आत्मनिर्भर खाने की दिशा में पहल की गई है। रासनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला कृषकों को ओएसटर मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रत्येक कृषक को 3 किलोग्राम मशरूम बीज उपलब्ध कराया गया। इस बीज से प्रत्येक कृषक द्वारा लगभग 25 से 30 बैग तैयार किए गए हैं जिससे उन्हें मशरूम उत्पादन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। कृषकों को मशरूम बीज 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया गया। एक बैग से लगभग तीन बार तक मशरूम की तोड़ाई की जा सकती है। बाजार में ओएसटर मशरूम की कीमत सामान्यतः 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक मिलती है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना है। मशरूम पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है जिसमें प्रोटीन फाइबर और आवश्यक खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पहल प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना तथा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के उद्देश्यों के अनुरूप किसानों को आधुनिक और लाभकारी कृषि गतिविधियों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना एक नवाचार के रूप में देखा जा रहा है जिससे विशेष रूप से महिला कृषकों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिल रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में इस प्रकार की नई तकनीकों और वैकल्पिक खेती को अपनाकर जिले के कृषक आय बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार ला रहे हैं।

मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



डिंडोरी। भारत सरकार द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मिशन लाइफ के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जनपद पंचायत समानापुर की ग्राम पंचायत भाजीटोला और कुकरांमठ में 14 मार्च 2026 को जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निदेशन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए दैनिक जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया जिसमें ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

नेशनल लोक अदालत: आपसी सामंजस्य से प्रकरणों का हुआ निराकरण

डिंडोरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शशिकान्ता वैश्य के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शशिकान्ता वैश्य कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया तथा अध्यक्ष अधिवक्ता संघ यूके पट्टेरिया द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश शशिकान्ता वैश्य ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित पारिवारिक विवाद मोटरवाहन दुर्घटना दावा चैक अनादरण तथा विभिन्न राजीनामा योग्य आपराधिक और दीवानी प्रकरण आपसी समझौते और सुलह के आधार पर निराकृत किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंकों की ऋण वसूली विद्युत विभाग के बकाया प्रकरण दूरभाष बिल बकाया तथा नगरपालिका के संपत्ति कर और जल कर से संबंधित प्रकरणों का भी उभय पक्षों



की सहमति से निराकरण किया जाता है। कार्यक्रम में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने नेशनल लोक अदालत के आयोजन पर बधाई दी और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। शुभारंभ कार्यक्रम में तृतीय जिला न्यायाधीश

कमलेश कुमार सोनी द्वितीय जिला न्यायाधीश शिवकुमार कोशल प्रथम जिला न्यायाधीश रविंद्र गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरजेश कुमार सनोडिया न्यायाधीश तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष कुमार केशरवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरपी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिया डहेरिया अध्यक्ष अधिवक्ता संघ यूके पट्टेरिया अध्यक्ष कर्मचारी संघ भीम प्रकाश रामटेके डिफेंस काउंसिल टीम के अधिवक्ता न्यायालयीन कर्मचारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी पक्षकार विद्युत विभाग नगरपालिका विभाग तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार केशरवानी ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 259 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 8240455 रुपये का अवाई पारित हुआ। प्रिलिमीनेशन प्रकरणों की श्रेणी में 74 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें विभागों को 1849579 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार लोक अदालत में कुल 10090034 रुपये का अवाई पारित किया गया।

डिंडोरी में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर कार्रवाई



डिंडोरी। खाद्य विभाग की टीम ने जिले में घरेलू उपयोग के एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों से कुल 10 सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान सहायक

आपूर्ति अधिकारी शमीम खान तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश तुरकर ने पुरानी डिंडोरी तिराहा स्थित मां रेवा होटल से 5 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। इसी तरह नकुल होटल से 3 तथा बस स्टैंड डिंडोरी स्थित मोले भोजनालय से 2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान इन सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर ही सभी 10 सिलेंडरों को जब्त कर डिंडोरी इंडेन गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिया गया। खाद्य विभाग द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियम आदेश 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है और इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन और लोकार्पण

डिंडोरी। शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के करकमलों द्वारा जनपद पंचायत डिंडोरी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा लोकार्पण संपन्न हुआ। जनपद पंचायत डिंडोरी अंतर्गत ग्राम अझवार में 39 लाख रुपये की लागत से बनने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी लैब भवन का भूमिपूजन किया गया। इसके साथ ही 3 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण भी किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बटीधा में 39 लाख रुपये की लागत से बनने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी लैब



भवन का विधिवत भूमिपूजन किया गया। ग्राम पंचायत घुसिया में 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भी विधिवत

जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न



डिंडोरी। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य मध्य प्रदेश में 01 मई से 30 मई 2026 के बीच किया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई डिण्डोरी में जिला एवं चार्ज स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए द्वितीय चरण का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भोपाल से आए जनगणना नोडल प्रभारी जयदीप नंदनवार तथा संजय सोनी ने प्रतिभागियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सीएमएमएस पोर्टल तथा एचएलबीसी वेब मैपिंग एप्लीकेशन के संबंध में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डेटा एंट्री तथा वेब मैपिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाते हुए अधिकारियों को व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया।

कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर अंजू भदौरिया के निर्देशन में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। साथ ही पोर्टल के विभिन्न फीचर्स का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया ताकि फील्ड में कार्य करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो। इस अवसर पर अपर कलेक्टर जेपी यादव डिप्टी कलेक्टर वैषनाथ चानिक एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा भारती मेरावी रामबाबू देवा डिप्टी कलेक्टर प्रियांशु जैन डिप्टी कलेक्टर डिगरसे सहित जिले के सभी तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।



न्यायालय की पहल से पति पत्नी के बीच हुआ समझौता सभी प्रकरण समाप्त

डिंडोरी। धरेलू विवाद के कारण वर्ष 2022 से अलग रह रहे पति पत्नी के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अंततः आपसी सहमति से समाप्त हो गया। दंपति की एक 5 वर्ष की पुत्री है और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा समय समय पर दोनों पक्षों को समझाइश दी जाती रही। जानकारी के अनुसार पत्नी ने वर्ष 2023 में भरण पोषण के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। वहीं पति की ओर से तलाक तथा पुत्री की कस्टडी को लेकर भी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। इन प्रकरणों की सुनवाई के दौरान न्यायालय तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा लगातार समझाइश देकर विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाता रहा। अंततः न्यायालय तथा अधिवक्ता गगन प्रकाश शुक्ल के निरंतर प्रयासों से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया और न्यायालय में लंबित सभी प्रकरण समाप्त कर दिए। बताया गया कि पुत्री के उज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह समझौता किया गया ताकि उसे माता पिता दोनों का स्नेह तथा मार्गदर्शन मिल सके।

ग्राम बुंदेला में कृषक पाठशाला आयोजित किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और योजनाओं की दी जानकारी



डिंडोरी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग डिंडोरी द्वारा विकासखंड करजिया के ग्राम बुंदेला में कृषक राम करण सिंह के खेत तथा ग्राम मुसुण्डा में कृषक आनंद कुमार के खेत पर कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों और शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कृषक पाठशाला में कृषि अभियांत्रिकी विभाग की उपयंत्र प्रोम कोराम ने किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने

नरवाई प्रबंधन आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग तथा कस्टम हायरिंग सेंटर की सुविधा के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती के कार्यों में समय श्रम और इंधन की बचत होती है तथा उत्पादन में वृद्धि संभव होती है। उन्होंने किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी शशि मरकम ने किसानों को विभिन्न शासकीय कृषि योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिवाई योजनाएं मशरूम उत्पादन के लिए आवेदन प्रक्रिया मूद्रा परीक्षण के महत्व तथा बलराम तालाब योजना के बारे में विस्तार से बताया और किसानों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील की गई तथा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ मूद्रा की उर्वरता भी बनी रह सके। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक कृषक उपस्थित रहे और कृषक पाठशाला से लाभान्वित हुए।

महिला स्वच्छता कर्मियों का किया गया सम्मान

शहपुरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर परिषद शहपुरा में स्वच्छता विषय पर एक ज्ञानवर्धक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। कार्यशाला में मुख्य वक्ता दमयंती सिंह ने महिलाओं की स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और समाज में उनकी अत्यंत भूमिका पर नगर परिषद द्वारा नगर की महिला स्वच्छता कर्मियों, स्वच्छता मित्रों के लिए



महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उनके सहयोग से ही स्वच्छ स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। इस अवसर पर नगर परिषद द्वारा नगर की महिला स्वच्छता कर्मियों, स्वच्छता मित्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नगर परिषद परिसर में उपस्थित महिलाओं का स्वच्छता एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष शालिनी

अरुण अग्रवाल ने नगर की नारी शक्ति और स्वच्छता कर्मियों की सराहना करते हुए उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में महिलाओं की भागीदारी प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में नगर परिषद उपाध्यक्ष मुकेश साहू पार्षद राजकुमारी रजक मीरा बनवासी मुख्या वक्ता दमयंती सिंह सीएमओ रीना राठौर स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर अश्विनी कुमार साहू सीएचओ देवेन्द्र साहू डीप वीरेंद्र पाल अंकिता नानपुरे वंदना कछवाहा मधु तिवारी ए राजा चक्रवर्ती सहित नगर की बड़ी संख्या में नारी शक्ति महिला स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता मित्र उपस्थित रहीं।

